

मुकदमों का विवरण

पुरूषोत्तमन बनाम

तमिलनाडु राज्य

(2023 की आपराधिक अपील No.3341) 30 अक्टूबर, 2023

[अभय **S.OKA** और पंकज मिठल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:जब अभियुक्त की सजा अपील पर निलंबित कर दी जाती है और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो क्या उच्च न्यायालय अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना जमानत रद्द कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** -धारा **389**-अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन; जमानत पर अपीलार्थी की रिहाई-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील-अभियुक्त की पर्याप्त सजा निलंबित कर दी गई और उसे जमानत पर बढ़ा दिया गया-जब अपील सुनवाई के लिए बुलाई गई, तो उच्च न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियुक्त की जमानत रद्द कर दी, क्योंकि अभियुक्त के वकील ने चार सप्ताह के स्थगन की मांग की-सच्चाई:

आयोजित किया गया:अभियुक्त द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की चूक के लिए, अपीलीय न्यायालय अभियुक्त को केवल इस आधार पर उसकी जमानत रद्द करने के लिए कार्यवाही करके दंडित नहीं कर सकता है कि उसके अधिवक्ता ने स्थगन की मांग की है और वह भी जमानत रद्द करने के मुद्दे पर उसे सुनने का अवसर दिए बिना-धारा 1 की उप-धारा के अंतर्गत 389, जेल अंतर्गत मौजूद अभियुक्त की सजा को निलंबित करते हुए, अपीलीय न्यायालय को अपील के अंतिम निपटारे तक अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाना पड़ता है-न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए भी अभियुक्त को कारण बताने के लिए नोटिस जारी कर सकती है कि जमानत क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए-किसी भी परिस्थिति अंतर्गत, किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं दी जाती है। 389(1) अभियुक्त को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना रद्द किया जा सकता है-किसी दिए गए मामले में, यदि अभियुक्त की ओर से पेश होने वाला अधिवक्ता असमर्थनीय पर स्थगन चाहता है और 182

अनुचित आधार पर, अपीलीय न्यायालय स्थगन के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने की अपनी शक्ति के भीतर है, और अपीलार्थी के कारण का समर्थन करने के लिए एक वकील नियुक्त करने का विवेकाधिकार रखता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय की ओर से इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और आरोपी को सजा के निलंबन और जमानत देने वाले पहले के आदेश को बहाल कर दिया जाता है-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 -एस. 6.[पैरा 5,7-10]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

बानी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 4 एस. सी. सी. 720:[1996] 3 पूरक।एस. सी. आर. 247-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता :2023 की आपराधिक अपील No.3341।

2017 के सी. आर. एल. ए. No.203 में मरदास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 07.07.2023 से।

रूप:

बी. करुणाकरन, अजीत विलियम एस., शंकर पी., एस. गौतम के लिए ईश्वर, एड.अपीलार्थी के लिए।

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री शुभी भारद्वाज, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अभय **S.OKA**, जे।

अनुमति दी गई।

2. पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना।

3. अपीलार्थी-अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था।अपीलार्थी द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 183 तक

पुरूषोत्तमन बनाम तमिलनाडु राज्य [अभय S.OKA, जे.] 184

12 जनवरी, 2018 के आदेश में अपीलार्थी की मूल सजा को निलंबित कर दिया गया था और उसे जमानत पर बढ़ाने का आदेश दिया गया था।

4. 7 जुलाई, 2023 को वर्ष 2017 की उक्त आपराधिक अपील को सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष बुलाया गया था। अपीलार्थी के वकील ने चार सप्ताह के लिए स्थगन की मांग की। केवल इस आधार पर कि अपीलार्थी जमानत की सुविधा का आनंद ले रहा है और उसके वकील ने स्थगन के लिए आवेदन किया है, उच्च न्यायालय जमानत को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा।

5. किसी मामले में, यदि अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता असमर्थनीय और अनुचित आधारों पर स्थगन की मांग करता है, तो अपीलीय न्यायालय स्थगन के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने की अपनी शक्ति के भीतर है। ऐसे मामले में, बनी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रमों में से एक को हमेशा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के पास अपीलार्थी के कारण का समर्थन करने के लिए एक वकील नियुक्त करने का विवेकाधिकार है जब अपीलार्थी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुचित आधारों पर अपील पर बहस करने से इनकार कर देता है। यद्यपि उच्च न्यायालय के पास अपील के गुणागुण पर विचार करने और गुणागुण के आधार पर निर्णय लेने का विकल्प है, उच्च न्यायालय हमेशा अपीलार्थी के कारण का समर्थन करने के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करने का पहला तरीका अपना सकता है। 6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389 की उप-धारा 1 (संक्षेप में "दंड प्रक्रिया संहिता") इस प्रकार है:

“389. अपील लंबित रहने तक सजा का निलंबन; जमानत पर अपीलार्थी की रिहाई-(1) किसी दोषी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपील को लंबित रहने तक, अपीलीय न्यायालय, उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए, आदेश दे सकता है कि सजा या आदेश के निष्पादन को निलंबित किया जाए और साथ ही, यदि वह कारावास में है, तो उसे जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाए।

बशर्ते कि अपीलीय न्यायालय, जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा करने से पहले, एक दोषी व्यक्ति जो मौत या आजीवन कारावास या दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के खिलाफ लिखित में कारण दिखाने का अवसर देगा:

1 (1996) 4 एससीसी 720

/

[2023] 14 एस सी आर।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां एक दोषी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाता है, लोक अभियोजक के लिए जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा। "

(रेखांकित आपूर्ति) 7. धारा 389 की उप-धारा 1 अंतर्गत जेल में रहने वाले अपीलार्थी-अभियुक्त की सजा को निलंबित करते हुए, अपील न्यायालय को अपील के अंतिम निपटारे तक अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाना होता है। धारा 389 की उप-धारा 1 का दूसरा परंतुक लोक अभियोजक को उप-धारा 1 के अंतर्गत दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। धारा 389 की उप-धारा 1 का दूसरा परंतुक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 की उप-धारा 2 के बराबर है। इसलिए, न्यायालय सुओ मोटू भी एक नोटिस जारी कर सकती है जिसमें आरोपी से कारण बताने के लिए कहा जा सकता है कि जमानत क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति अंतर्गत, धारा 389 की उप-धारा 1 के अंतर्गत किसी आरोपी को दी गई जमानत को आरोपी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना रद्द नहीं किया जा सकता है।

8. दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने जमानत रद्द करने के मुद्दे पर अपीलार्थी-अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना, उसे दी गई जमानत को तुरंत रद्द करने के लिए आगे बढ़ गया है। उच्च न्यायालय की ओर से इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब उच्च न्यायालय हमेशा उस स्थिति से निपट सकता है जब अनुचित आधारों पर अपील की अंतिम सुनवाई के समय अभियुक्त के लिए अधिवक्ता द्वारा स्थगन की मांग की जाती है। अभियुक्त द्वारा नियुक्त अधिवक्ता की चूक के लिए, अपीलीय न्यायालय अभियुक्त को केवल इस आधार पर उसकी जमानत रद्द करने के लिए कार्यवाही करके दंडित नहीं कर सकता है कि उसके अधिवक्ता ने स्थगन की मांग की है और वह भी जमानत रद्द करने के मुद्दे पर उसे सुनने का अवसर दिए बिना।

9. हम ऐसे मामलों में आए हैं जहां सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आरोपी के वकील ने योग्यता के आधार पर अपील पर बहस करने से इनकार कर दिया था। जब केवल सजा के निलंबन के लिए आवेदन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, तो आरोपी के वकील से अपील पर बहस करने के लिए तैयार होने की उम्मीद नहीं की जाती है।

10. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और अपीलार्थी को सजा के निलंबन और जमानत देने वाले 12 जनवरी, 2018 के पहले के आदेश को बहाल कर दिया जाता है।

185

पुरूषोत्तमन बनाम तमिलनाडु राज्य [अभय S.O.K.A, जे.]

11. हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि अपीलकर्ता किसी अनुचित या अनुचित आधार पर स्थगन के लिए आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय के लिए बानी सिंह 1 के मामले में निर्धारित विकल्पों में से एक का सहारा लेकर अपील के साथ आगे बढ़ना हमेशा खुला रहेगा।

12. तदनुसार अपील की अनुज्ञात जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

निधि जैन